बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 232 ● नई दिल्ली ● वीरवार 02 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

पालतू कुत्ते सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य है, डॉग कस्टडी विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई में कहा था कि पालतू जानवरों को मात्र संपत्ति नहीं माना जा सकता। अदालत ने पालतू कुत्तों की कस्टडी विवाद में उनके कल्याण और भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता देते हुए तीन कुत्तों को उनके गोद लेने वाले मालिकों को वापस सौंपने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने अप्रैल में ट्रायल कोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए यह फैसला सुनाया था। मामले में पुलिस ने क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत छापा मारा था, जहां कुत्तों को खराब हालत में पाया गया। बचाए गए तीन टॉय पमेरेनियन कुत्तों (मिष्ठी, कोको और कॉटन) को एनजीओ के माध्यम से गोद लेने वालों को सौंपा गया था।

अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर तीखा हमला किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने इस मामले को संभालने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाए और दावा किया कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी, तब तक कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी। उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब राम मंदिर दान में कथित चोरी के मामले की जांच चल रही है और कई आरोपियों को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकारें इस मामले में आरोपी लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा, अगर आप चाहते है कि चंदा चोरों को सज़ा मिले, तो सरकार बदलनी होगी। मौजूदा केंद्र सरकार और राय सरकार सज़ा सुनिश्चित नहीं कर सकतीं। भगवान राम का हर भक्त जो चाहता है कि चंदा चोरों को सज़ा मिले, उसे सरकार बदल देनी चाहिए। जब बार एसोसिएशन ने उनका बहिष्कार किया तो मुझे खुशी हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए सनातन का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। यह दावा करते हुए कि बीजेपी नेता भगवान राम को सच में भगवान नहीं मानते, केजरीवाल ने कहा कि ये लोग राम को भगवान नहीं मानते; वरना वे चोरी नहीं करते। भगवान

राम ने उन्हें सब कुछ दिया है। उन्होंने 21 राज्यों और केंद्र में सरकार बनाने में उनकी मदद की। उन्हें कम से कम जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने आगे आरोप लगाया, देश का हर सनातनी दुखी और परेशान है। अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। उन्होंने सनातन का इस्तेमाल सिर्फ़ सत्ता और पैसे के लिए किया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी सनातन में सच्ची आस्था है। उन्होंने कहा, सिर्फ़ आम आदमी पार्टी की ही सनातन में सच्ची आस्था है। हमने लोगों के लिए मुफ़्त तीर्थयात्रा का आयोजन किया। पंजाब में काली और लव-कुश को समर्पित एक मंदिर बनाया जा रहा है। हम भजन संध्याओं का आयोजन कर रहे हैं। हम लोगों को भ्रष्टाचार-मुक्त शासन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ही देश की सच्ची सनातनी पार्टी है। केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और दावा किया कि प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से वे राम मंदिर नहीं गए हैं। केजरीवाल के अनुसार, प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को लगभग ढाई साल बीत चुके हैं, लेकिन शाह इस दौरान मंदिर नहीं गए हैं। केजरीवाल ने कहा श्री राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा को ढाई साल यानी कुल 891 दिन बीत चुके हैं। इन ढाई सालों में गृह मंत्री अमित शाह एक बार भी राम मंदिर नहीं गए। जिस व्यक्ति ने भगवान राम के नाम का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है, वह राम मंदिर नहीं गया है। मैंने इंटरनेट पर देखा, ChatGPT से पूछा, पत्रकारों से बात की और अमित शाह की टाइमलाइन देखी। उन्होंने अपने भाषणों और इंटरव्यू में 42 से ज्यादा बार राम मंदिर का ज़िक्र किया है और उसके नाम पर वोट मांगे हैं। उनके पास राम के नाम पर वोट मांगने का तो समय है, लेकिन मंदिर जाने का समय नहीं है।

इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, अमित शाह से मेरे सवाल हैं- आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्या आपका राम मंदिर जाने का मन नहीं करता? क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है? क्या आप राम को भगवान नहीं मानते? केजरीवाल ने शाह से मंदिर जाने का आग्रह भी किया और कहा, मैं अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि वे ज़रूर राम

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने हमारे स्मारक, हमारा गौरव के तहत दो नई हेरिटेज योजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को हमारे स्मारक, हमारा गौरव के तहत दो नई हेरिटेज संरक्षण योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की। इसके तहत प्राइवेट संस्थान स्मारकों को अडॉप्ट कर सकेंगे और रेस्टोरेशन के लिए 2 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल का मकसद जन भागीदारी के ज़रिए संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि हर पीढ़ी ने दिल्ली को अपने अनोखे अंदाज़ में अनुभव किया है; कुछ लोगों ने किताबों के ज़रिए इसके स्मारकों के बारे में जाना है, तो कुछ ने उन्हें खुद देखा है। दिल्ली की हर पीढ़ी ने इस शहर को अपने तरीके से जिया है। कुछ लोगों ने इन स्मारकों के बारे में किताबों में पढ़ा है, तो कुछ ने इन्हें करीब से देखा है। अब समय आ गया है कि इस विरासत को और संवारा जाए और अगली पीढ़ी को सौंपा जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ-साथ विरासत के विज़न को आगे बढ़ाते हुए, दिल्ली सरकार ने हमारे स्मारक, हमारा गौरव अभियान के तहत दो नई योजनाओं को मंजूरी दी है, दिल्ली CM ने X पर लिखा। उन्होंने आगे कहा, अब, प्राइवेट कंपनियाँ, PSU, ट्रस्ट और NGO दिल्ली के 75 ऐतिहासिक स्मारकों को 5 साल के लिए मॉन्यूमेंट फ्रेंड्स के तौर पर अडॉप्ट कर सकेंगे। साथ ही, योग्य संस्थानों को स्मारकों के मुख्य संरक्षण और रेस्टोरेशन के लिए 2 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी। जन भागीदारी के ज़रिए, दिल्ली की विरासत को नई पहचान और नए गौरव के साथ जीवंत सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह बात दिल्ली कैबिनेट द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद कही गई, जिसके तहत NGO सहित प्राइवेट संगठन इसके 75 स्मारकों को अडॉप्ट करेंगे। इस पहल के तहत, इन स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के लिए उन्हें ट्रस्ट, NGO, फ़ाउंडेशन और संस्थानों को सौंपने की एक योजना भी शुरू की जाएगी इससे पहले, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर, अपनी पहचान प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। यह प्रोजेक्ट पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राय व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की एक संयुक्त पहल है, जिसका मकसद पूरे भारत में धरोहर और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करना है।

उत्तम नगर में विजय सेल्स शोरूम धू-धू कर जला, लाखों रुपये का सामान जलकर खाक, दमकलकर्मी मौके पर

नई दिल्ली । दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की लपटों और काले धुएं के गुबार ने आसमान को ढक लिया। आग लगने से स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नजफगढ़ रोड पर विजय सेल्स की बिल्डिंग में आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा शोरूम धू-धूकर जलने लगा। आसमान में काला धुआं छा गया, जिससे आसपास का इलाका पूरी तरह से प्रभावित हुआ। आग लगने से स्थानीय निवासियों में अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी फौरन घटनास्थल पर पहुंच गए। दमकलकर्मी को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि, शोरूम में रखे लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल फायर अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने कहा, आग कैसे लगी ये जांच का विषय है। हमारे पास ये सूचना 04.15 बजे आई थी। यह इलेक्ट्रॉनिकल सामान का शोरूम है जिसमें आग लगी है। 15 गाड़ियां मौके पर हैं। आग बुझा ली गई है और कूलिंग ऑपरेशन जारी है। अभी तक कोई हताहत की खबर नहीं है। दमकल विभाग के अनुसार, उत्तम नगर स्थित मेट्रो पिलर संख्या 663 के पास बने विजय सेल्स शोरूम में आग लगी थी। शुरुआती चरण में तीन दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए कुल 15 दमकल वाहनों को मौके पर लगाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, आग पर सुबह करीब 6:30 बजे पूरी तरह काबू पा लिया गया। इसके बाद दमकल कर्मियों ने कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा, जो सुबह तक चलता रहा। करीब 350 वर्ग गज क्षेत्र में बने बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और तीन मंजिला भवन में आग लगी थी। आग से इलेक्ट्रॉनिक सामान, विद्युत उपकरण, फर्नीचर और अन्य सामान जल गए। दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है।

जनसांख्यिकीय बदलावों पर हाई लेवल कमेटी मंत्रालयों से लेगी सुझाव, शाह ने जल्द सिफारिशें देने का दिया सुझाव

नई दिल्ली । जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान शाह ने कमेटी को कई सुझाव दिए हैं। हाई लेवल कमिटी द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों से भी फीडबैक लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कमेटी को जल्द सिफारिशें देने का सुझाव दिया है। हाई लेवल कमिटी ने गृह मंत्री को बताया कि वह ज़मीनी स्तर की सीधी जानकारी हासिल करने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों का दौरा करेगी। हाई लेवल कमिटी ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों को अधिक सार्थक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए, उनसे ज़रूरी जानकारी पहले से प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार कर ली गई है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाई लेवल कमिटी द्वारा बनाई गई रणनीति की सराहना करते हुए गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे समिति को उसके रोजमर्रा के कामकाज और दौरों के दौरान हर संभव सहायता प्रदान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त, 2025 इस कमेटी के गठन की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने और उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) इस समिति के अध्यक्ष हैं। जनगणना आयुक्त के अलावा, तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति दुर्गा शंकर मिश्रा (रिटायर्ड आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव (रिटायर्ड आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि (सदस्य पीएमईएसी), समिति के सदस्य हैं। यह हाई लेवल कमिटी देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का वैज्ञानिक रूप से आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और उचित नीतिगत, विधायी तथा प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करेगी।

पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 11 साल पूरे होने पर खुशी जताई, कहा- इसका असर बदलाव लाने वाला है

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को डिजिटल इंडिया पहल के 11 साल पूरे होने पर कहा कि 1 जुलाई 2015 को शुरू हुए इस प्रोग्राम ने देश भर के नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया है। इस खास मौके पर X पर अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जब एक अरब से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, तो इसका असर बदलाव लाने वाला होता है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि इस पहल के शुरू होने के बाद से भारतीयों ने मोबाइल बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन गवर्नेंस सेवाओं तक, डिजिटल टूल्स को किस बड़े पैमाने पर अपनाया है। एक और पोस्ट में PM मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया के 11 सालों की सफलता ने भारत को दुनिया भर में एक नई पहचान दी है। यह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के देशवासियों के संकल्प को दिखाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू रखता है, वही विज्ञान का सच्चा सारथी है। वह यात्रा के अंत तक पहुँचता है और विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। PM ने आगे कहा, डिजिटल इंडिया एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मज़बूत नींव है। पिछले 11 सालों में, इसने गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के साथ-साथ नागरिकों का जीवन आसान बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार से लेकर डिजिटल ट्रांज़ैक्शन तक, इस अभियान की अभूतपूर्व सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। पिछले दशक में, डिजिटल इंडिया भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव बन गया है। भारत अब ग्लोबल रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे है, जिसमें UPI दुनिया भर के ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम का लगभग 49व संभालता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की GDP में लगभग 12-14% का योगदान देती है। उम्मीद है कि अगले दशक में यह लगभग पांचवां हिस्सा (20%) योगदान देगी।

डिजिटल इंडिया ने अलग-अलग सेक्टर में इनोवेशन, स्टार्टअप की ग्रोथ और टेक्नोलॉजी को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाई है। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में भारत की क्षमता को भी मज़बूत किया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज़ के अनुसार, जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया पूरे देश में समावेशी विकास, टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भरता और नागरिकों को सशक्त बनाने का काम जारी रखे हुए है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को 9 स्तंभों (पिलर्स) के आधार पर बनाया गया था ताकि डिजिटल एक्सेस को बढ़ाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत ढांचा तैयार किया जा सके। इनमें ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सबकी पहुँच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई-गवर्नेंस, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, नौकरियों के लिए IT और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम शामिल हैं। ये 9 स्तंभ डिजिटल इंडिया के लिए रणनीतिक ढांचा प्रदान करते हैं और एक जुड़े हुए और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र की नींव रखते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम डिजिटल अंतर को पाटने की एक पहल से विकसित होकर दुनिया के सबसे बड़े DPI इकोसिस्टम में से एक बन गया है, जो अलग-अलग सेक्टर में गवर्नेंस को मज़बूत कर रहा है। इस पहल ने पब्लिक हेल्थकेयर सेक्टर को भी बेहतर बनाया है। पिछले दशक में, डिजिटल इंडिया ने सेवाओं को तेज़, अधिक जुड़ा हुआ और आसानी से उपलब्ध बनाकर पब्लिक हेल्थकेयर में बदलाव किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम मरीज़ों को डिजिटल रूप से अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा देता है, जिससे लाइन और कागज़ी काम कम हो जाते हैं। 24 जून 2026 तक, ORS में 1.37 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दर्ज किए गए हैं। एक रिलीज़ के अनुसार, इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हुए क्लाउड-आधारित eHospital प्लेटफ़ॉर्म अस्पताल के कामकाज को डिजिटल बना रहा है, जबकि eBloodBank हेल्थकेयर संस्थानों में खून की उपलब्धता और प्रबंधन में सुधार कर रहा है स्केलेबल और नागरिक-केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म की बदौलत भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। फरवरी 2026 तक, भारत ने इंडिया स्टैक और DPI सिस्टम पर सहयोग के लिए 24 देशों के साथ MoU साइन किए हैं, जिनमें डिजिटल पहचान, पेमेंट, डेटा एक्सचेंज और सेवा वितरण शामिल हैं। UPI अब UAE, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका सहित आठ से ज्यादा देशों में चालू है, जिससे ग्लोबल फिनटेक में भारत की मौजूदगी मज़बूत हो रही है। आधार, डिजिलॉकर, कोविन , GeM, दीक्षा , उमंग और ई-संजीवनी जैसे प्लेटफ़ॉर्म अंतरराष्ट्रीय डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को तेज़ी से आकार दे रहे हैं। 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने इंडिया स्टैक ग्लोबल और ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी भी लॉन्च किए।

सम्पादकीय...

ईवी नीति

देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या काफी विकट रूप ले चुकी है। राजधानी की भौगोलिक स्थिति और अलग-अलग जलवायु परिस्थितियां इस समस्या को और बढ़ा देती है। हालांकि प्रदूषण के लिएअनुचित तरीके से की गई मानव गतिविधियां भी जिम्मेदार है। हर साल सर्दियों के शुरू होते ही दिल्ली एक घने धुएं और धुंध की चादर में लिपट जाती है और वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। इस बार तो गर्मियों में भी वायु गुणवत्ता का स्तर कई बार खतरनाक स्तर पर देखा गया। दिल्ली वाले लगभग पूरे साल ही प्रदूषित और अस्वस्थ हवा में सांस लेते है। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि पिछले 11 वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को पार करने वाले दिनों की संख्या बढ़ रही है। प्रदूषण के स्रोतों और विभिन्न वजहों के योगदान को समझने के लिए कई अध्ययन किए गए है। परिवहन उद्योग, पावर प्लांट, सड़क की धूल और निर्माण यह पांच प्रमुख कारणों जो दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान देते है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर पहचाने जाने के बाद ही दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के मुद्दे पर ध्यान देना शुरू किया गया। हालांकि प्रदूषण कम करने के लिएकई उपाय किएगएलेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में लगभग 33 प्रतिशत प्रदूषण कमर्शियल वाहनों और 46 प्रतिशत टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से होता है। जो कमर्शियल गुड्स व्हीकल दिल्ली में हैं वह एन-1 कैटेगरी के हैं, जिन्हें साढ़े तीन टन तक का छोटा ट्रक कहा जाता है। महानगर में जिस तरह से कारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उससे पैट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से प्रदूषक तत्वों का भारी उत्सर्जन हो रहा है। कारें हर मध्यम परिवार के लिए जरूरत से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस बार सर्दियों के आगमन से काफी पहले ही दिल्ली वासियों को शुद्ध हवा में सांस दिलवाने के लिए नीतियों को व्यावहारिक रूप से लागू करने का काम शुरू कर दिया है। पूर्व की सरकारें तभी जागती थी जब दिल्ली में सांस लेना दूभर हो जाता था।

रेखा गुप्ता सरकार ने अब राजधानी में इलैक्ट्रिक वाहनों को नई रफ्तार देने के लिएनई इलैक्ट्रिक व्हीकल नीति की घोषणा की है। इस नीति से प्रदूषण कम होगा और राजधानी में स्वच्छ परिवहन को मजबूती मिलेगी। नई नीति एक जुलाई से ही लागू की जा रही है जो 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत सरकार अगले 4 वर्षों में करीब 15 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस बड़े बजट के जरिए इलैक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएगी।नई पॉलिसी के तहत सरकार इलैक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर पहले साल 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि, दूसरे साल में 20,000 रुपये और तीसरे साल में 10,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं पैसेंजर थ्री-व्हीलर के लिए ये राशि सालाना आधार पर क्रमश: पहले साल में 50,000 रुपये, दूसरे साल में 40,000 रुपये और तीसरे साल में 30,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा एन 1 कैटेगरी यानी छोटे इलैक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर ग्राहकों को पहले साल 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी जिस दिन लागू होती है उसके 3 महीने के अंदर साढ़े 3 टन से 12 टन तक के एम2 कैटेगरी के ट्रक्स को जो एंट्री फ्री दी जाएगी लेकिन ये नियम केवल पहले 1,000 इलैक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर ही लागू होगा। सरकार ने इस ईवी पॉलिसी में पुराने और कबाड़ हो चुके वाहनों के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का भी ऐलान किया है। ताकि लोग अपने पुराने वाहन (जो अपनी तय उम्र पूरी कर चुके हों) उन्हें स्क्रैप करा सकें। सरकार का कहना है कि पुराने बीएस 4 या उससे भी नीचे के इमिशन नॉर्म्स वाले पुराने टू-व्हीलर को स्क्रैप में भेजने पर वाहन मालिक को 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस तरह दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जो इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी नीति लेकर आई है। पिछले दो दशकों में प्रशासन द्वारा मोटर वाहनों से उत्सर्जन को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साल 2001 में सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों (बसों, ऑटो और टैक्सियों) को पैट्रोल/डीजल से कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) आधारित प्रणाली में बदल दिया गया था। सीएनजी को इसकी स्वच्छ विशेषताओं के कारण ही प्राथमिकता दी गई थी। 2015 में डीजल से चलने वाले कमर्शियल व्हीकल (वाणिज्यिक वाहनों) जैसे ट्रक पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया गया था, जो अन्य राज्यों में जाने के लिए शॉर्ट-कट के तौर पर सड़कों का इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली शहर में प्रवेश कर रहे थे। ऐसे वाहनों को अब रिजनल रिंग रोड कॉरिडोर का इस्तेमाल करना होता है, जिसे दिल्ली के आसपास विकसित किया गया है। पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की नीति के तहत एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 15 साल पुराने पैट्रोल वाहनों पर भी रोक लगा दी थी। देशका आटोमोबाइल सैक्टर अब इलैक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ा रहा है और लोग भी इन्हें अपनाने लगे हैं लेकिन देश में अभी चार्जिंग स्थलों का ढांचा व्यापक रूप से स्थापित नहीं हो पाया। इसलिए चार्जिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए पैट्रोल पम्पों की तरह जगह-जगह चार्जिंग केन्द्र स्थापित करने की जरूरत है तभी ईवी नीति सफल होगी। कौन नहीं जानता कि प्रदूषण के चलते दिल्लीवासी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और छोटे बच्चों के फेफड़े भी अब गुलाबी की बजाय काले रंग में परिवर्तित हो रहे हैं। हालांकि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिएआसपास के राज्यों में पराली जलाना भी एक कारणहै। दिल्ली में लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। इसके लिए जनता की भागीदारी की बहुत जरूरत है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की पहल सराहनीय होने के साथ-साथ अनुकरणीय भी है। इसलिए दिल्ली वासियों का यह दायित्व है कि वह प्रदूषण नियंत्रण अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं और स्वयं भी प्रदूषण कम करने के लिए प्रकृति के साथ जीना सीखें।

आज़ादी के आंदोलन के हर चरण में किसान सभा का योगदान रहा

अनीश अंकुर

क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 76 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राघवपुर (बिहटा) में श्री सीताराम आश्रम में विमर्श का आयोजन किया गया। विषय था आजादी के आंदोलन में किसान सभा की भूमिका। इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों और कस्बों के किसान व उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। स्वागत वक्तव्य अभिषेक कुमार ने किया जबकि पूरे कार्यक्रम का संचालन पटना जिला किसान सभा के सचिव गोपाल शर्मा ने किया। विषय प्रवेश करते हुए श्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष व स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्येता कैलाश चंद्र झा ने अपने वक्तव्य में बताया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1927 में पटना पश्चिमी किसान सभा की स्थापना की थी। यही सभा आगे चलकर 1929 में बिहार राज्य किसान सभा तथा 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में विकसित हुई। यह स्वतंत्रता आंदोलन के बीच की कहानी है। इस किसान सभा को जवाहर लाल नेहरू का समर्थन था। नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन सबमें किसान सभा के लोग शरीक रहे। मतभेद शुरू हुआ 1942 में जब पीपुल्स वार की लाइन आई। स्वामी जी ने कई राजनीतिक मसलों पर स्टैंड लिया। इस बीच कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य आपस में मतभेद उभरने लगे। 1942 में क्या हो रहा था यह गहन शोध का विषय है जिसपर काम किया जाना बाकी है। मेरा और वाल्टर हाउजर का मानना है कि किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी और जयप्रकाश नारायण के बीच बंट गई। भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर भी अलग अलग राय उभर कर आ गई। मुझे हाल में हजारीबाग जेल में जाने का मौका मिला वहां मैंने देखा कि राहुल जी का मेल मौजूद था लेकिन स्वामी जी का कोई चिह्न बचाकर नहीं रखा गया है। 1937 में जब पहली बार मंत्रिमंडल बना तो सबसे पहला मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस को बनाया गया श्री कृष्ण सिंह दूसरे मुख्यमंत्री थे। ये बात आजकल कम लोग जानते हैं। जन संस्कृति मंच में राज्य अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करते हुए हुए कहा प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर का अंत हो गया। इस्लाम के खलीफा का अंत कर दिया। महात्मा गांधी ने अच्छी डिप्लोमेसी करते हुए मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिए खलीफा का सपोर्ट किया। स्वामी सहजानंद असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से जुड़ जाते हैं। पटना पश्चिमी किसान सभा के माध्यम से किसानों की मुक्ति की लड़ाई शुरू की साम्राज्यवाद, जमींदार, छूआछूत, वर्णवाद इन सबसे लड़ाई लड़ने की ठानी। ब्राह्मणों से प्रतिष्ठा दिलाने के लिए बनारस से बिहटा तक के लड़ाई लड़ी। वे पौरोहित्य के खिलाफ लड़ने को प्रेरित कर रहे थे। स्वामी जी ने मेरा जीवन संघर्ष किताब में बताया कि कैसे बेगारी करवाई जाती थी। स्वामी जी ने हथुआ महाराज के खिलाफ एक धोबी को खड़ा कर दिया था। पुलिस हथुआ महाराज के खिलाफ काम करते हुए वोटरों को वोट देने रोका करते थे। स्वामी जी को यह एहसास हुआ कि पाखंड से भी मुक्ति जरूरी है। देश से मुक्ति के साथ-साथ जमींदारों, छद्म धार्मिकता से मुक्ति चाहिये। सबसे पहला जमींदारी उन्मूलन कानून बिहार में पास हुआ। दरभंगा महाराज ने केस कर दिया बाद में भारतीय संविधान में पहला संशोधन जवाहर लाल के मदद से किया गया। बिहार राज्य किसान महासभा के उमेश सिंह ने बताया -आज देश का सबसे बड़ा जमींदार अडानी है जो सोलह लाख एकड़ जमीन का मालिक है। इतनी जमीन तो आजतक किसी जमींदार के पास नहीं रही है। विकास के नाम पर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

कोरोना के समय पर तीन काले कानून लाकर हमारी खेती, उत्पाद पर कब्जा करने का प्रयास किया गया लेकिन उसके खिलाफ भारत भर के किसानों ने संघर्ष किया। दुनिया के इतिहास में फ्रेंच क्रांति के बाद यह किसानों की सबसे बड़ी गोलबंदी कही जाती है। जब देश के किसानों ने राजधानी को चारों ओर से घेर कर 13 महीने तक लड़ाई लड़कर काले कानूनों को वापस लेने पर मजबूर कर दिया गया। अभी वर्तमान सरकार सैटेलाइट टाउनशिप का कानून लाई है। यह अब तक का सबसे बड़ा भूमि हड़प आंदोलन है। अकेले पटना जिला में 81 हजार एकड़ कब्जा किया गया है। सरकार इसको विकास का नाम देकर 'लैंड पुलिंग' कह रही है। खेती भूमि का नाश किया जा रहा है। अब गौतम अडानी बिहार में निवेश की बात कर रहे हैं। बिहार में खेती भूमि के अलावा तो कुछ भी नहीं है। जिस राज्य में हाइवे निर्माण के नाम पर चार लाख पचपन हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया। मुआवजा नहीं दिया जाता है विरोध करने पर पुलिस सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का नाम देकर जेल में डाल देती है। बगीचा, पेड़ कटने के नाम पर प्रकृति बैलेंस खत्म हो रहा है। प्रतिकार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्वामी जी की तरह कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। पेशे से अधिवक्ता ज्ञानचंद भारद्वाज ने अपने गांव दहिया से स्वामी जी से संबंध के बारे में बताया स्वामी जी ने हमारे गांव में लाइब्रेरी और शिक्षा का प्रसार किया करते थे। हमारे गांव में संस्कृत विद्यालय खोला गया यह आजकल हाईस्कूल बन गया है। किसान आंदोलन उसका शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से भी जुड़ा हुआ रहा है। किसी भी आंदोलन की सफलता तभी होती है जब साथ-साथ सुधार आंदोलन भी चलता है। जब हमारे गांव में ब्राह्मण लोगों ने पुरोहित का काम छोड़ दिया तो खगड़िया के संस्कृत विद्यालय से लाकर काम शुरू किया। समाज के सुधार आंदोलन पर मौलिक रूप से काम शुरू किया। बेगूसराय के हमारे इलाके में नौ सत्ता घर होता है इसे बनाने के लिए, स्वामी जी के अनुसार, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह है की किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जब तक सरकारी स्कूल नहीं होगा और इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी पुस्तकालय अंग्रेजों से छुपकर मीटिंग करने की जगह थी। सही मायने में राष्ट्र भक्त किसान है। आज बिड़ला और आर. एस. एस दोनों के स्कूल का फीस एक ही है।

बिहार राज्य किसान सभा के रवींद्र नाथ राय ने अपने संबोधन में कहा 1857 में चलने वाले आंदोलन किसानों के आंदोलन थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में शामिल होने वाले सिपाही कौन थे वे तो वर्दी पहने हुए किसान थे। उससे पहले आदिवासियों का आंदोलन भी दरअसल किसानों का आंदोलन ही था। भगत सिंह के चाचा किसानों के नेता थे। जालियांवाला बाग में मरने वालों में विभिन्न गावों से आए हुए किसानों के बेटे थे। चौरा-चौरी की घटना में मरने वाले किसान थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों को केंद्रीय भूमिका में लाते हैं। उन्होंने जो किसान सभा बनाई वह संगठित लड़ाई की शुरुआत थी। कांग्रेस के नेतृत्व में बड़े जमींदार थे। स्वाधीनता आंदोलन के बीच में किसानों के आंदोलन को खड़ा किया यदि स्वामी जी के नेतृत्व में किसान आंदोलन नहीं होता तो भारत का संविधान पूंजीपतियों और जमींदारों का बनता। आज बिहार में जमीन छीनने की तैयारी चल रही है और कोई आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। जब जमीन जाने की बात हुई तो पंजाब के किसानों में उबाल आया पर बिहार के किसानों में नहीं आया। मन बात तो यह है कि आज किसानों को किसानी से मुहब्बत नहीं रह गई है। भारत के जितने कृषि नीति बनी है 1967 के बाद वह अमेरिकी कंपनियों द्वारा बनाई गई है। कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम तक को अमेरिकी हितों के अनुरूप बनाया गया है। पूरी कृषि पद्धति को नष्ट कर दिया गया है। आज की लड़ाई जमींदारों के बदले कॉरपोरेट के इशारे में बनने वाली नीतियों से है। सभा को संबोधित करने वाले अन्य वक्ताओं में थे गोरखरी गांव के लवकुश शर्मा, अमहरा के सुधीरशरण, रातरी गांव के कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा तथा पटना सिटी किसान सभा के अध्यक्ष वशिष्ठ शामिल थे। धन्यवाद ज्ञापन सुधांशु कुमार ने किया। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोगों में थे अनीश अंकुर, विक्रम से लवकुश शर्मा, नौबतपुर से निर्मल कुमार सोनू, वशिष्ठ, पटना से आए उदयन राय, बिसनपुरा से संतोष, अमहारा से अमित शर्मा, महेश प्रसाद, दारा, शैलेश कुमार, महेश प्रसाद, सुधीर सिंह, मुन्ना सिंह, वैभव, गंगाचक के गोपाल जी, कौड़िया के समुनी, सूर्यदेव आदि थे। इस मौके पर 'दीक्षा फाउंडेशन' द्वारा चलाए जा रहे स्कूल के बच्चों द्वारा एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छोटे-छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया था। जिस किस्म की कृतियां शामिल थी उसमें प्रमुख है मधुबनी पेंटिंग, जूट पेंटिंग, बम्बू स्टैंड, क्लॉथ बैग, ट्रे, पॉट लाइट, फ्रिज मैग्नेट, ज्वेलरी आइटम, कैनवास पेंटिंग। शामिल बच्चों में सृष्टि, ईशिका, नंदिनी, सलोनी, मुस्कान, अनुप्रिया शर्मा, सोनाली, आदित्य, आनंदी, आयुष, शिवम, अंकित, प्रज्ञा, प्रिया, विष्णु आदि थे।

हिन्द महासागर की अर्थ-नीति

अगर हम विश्व इतिहास पर नजर डालें तो पिछली सदियों का इतिहास दुनिया के तमाम देशों पर कुछ चुनिन्दा यूरोपीय देशों के साम्राज्यवादी आधिपत्य का इतिहास रहा है और इस बीच तुर्की में स्थापित शक्तिशाली उस्मानिया साम्राज्य के वर्चस्व की गाथा भी कहता रहा है। दूसरी तरफ यह दौर विश्व में औद्योगिक क्रान्ति का भी दौर रहा है जिसके चलते यूरोपीय देशों ने अपनी व्यापार बुद्धि के बल पर एशिया व अफ्रीका समेत दूसरे महाद्वीपों के देशों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया और इनके समुद्री मार्गों पर अपना कब्जा जमाया। इनमें ब्रिटेन से लेकर फ्रांस व नीदरलैंड से लेकर पुर्तगाल जैसे देश शामिल थे। इनमें से ब्रिटेन पहले नम्बर पर था जिसने अमरीका जैसे देश तक पर अपना राज कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, परन्तु कालान्तर में 17वीं सदी में ही ब्रिटेन को इस देश से अपना कब्जा छोड़ना पड़ा, परन्तु इसके बाद एशिया व अफ्रीका के अधिसंख्य देशों पर इसका कब्जा बना रहा। इस सन्दर्भ में यह नहीं भूलना चाहिए कि 17वीं सदी के शुरूआती दौर में ही अंग्रेजों को नजर भारत पर पड़ी और उसने इसके साथ व्यापार करने के रास्ते खोजने शुरू किये जिसके चलते मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने भारत में व्यापार करने का शाही फरमान जारी कराया। इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उस समय भारत का विश्व व्यापार में क्या हिस्सा रहा होगा, क्योंकि 1756 में जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पलासी युद्ध में छल-बल से हराया तो विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 24 प्रतिशत के लगभग था। उस समय तक मुगलिया सल्तनत ढह चुकी थी और पूरे भारत में देशी राजे-रजवाड़ों की स्वायत्तता सिर चढ़ कर बोल रही थी, परन्तु इसके बाद जब औद्योगिक क्रान्ति का दौर शुरू हुआ तो साम्राज्यवादी यूरोपीय ताकतों ने दुनिया के प्राकृतिक आय स्रोतों से सम्पन्न व समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए जरूरी बने देशों को कब्जाना शुरू किया जिससे वे अपने देश में बने माल की समुचित खपत कर सकें और इन देशों में उपलब्ध खनिज सम्पदा का अधिकाधिक दोहन अपने लाभ में कर सकें। इस क्रम में भारत की भौगोलिक स्थिति अंग्रेजों के लिए आदर्श साबित हुई, जहां से बैठ कर उन्होंने पूरे पश्चिम एशिया का शासन संचालित किया। इसके लिए, सबसे पहले तुर्कों के उस्मानिया साम्राज्य का ढहना जरूरी था जिसे उन्होंने 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया। तब तक भारत पर अंग्रेजों का पुख्ता राज कायम हो चुका था और अमेरिका भी अपनी ताकत के बूते पर विश्व व्यवस्था में अपनी जगह बना चुका था। इस युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपनी सुविधा के अनुसार एशिया व अफ्रीकी देशों का भौगोलिक निर्धारण किया खास कर पश्चिम एशियाई देशों का क्योंकि तब तक इन देशों में इनकी धरती के गर्भ में छिपे खनिज तेल की खोज होने लगी थी, परन्तु विश्व क्रम के इस बदलाव के बाद जर्मनी में भी औद्योगिक क्रान्ति के चलते अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई और इसके तानाशाह बने नेता हिटलर ने विश्व विजेता बनने की ठान ली, परन्तु इसके समानान्तर रूस में ऐसा बदलाव हो रहा था जिसमें दुनिया के औपनिवेशिक देशों में अपने बूते पर शासक वर्ग के खिलाफ विद्रोह करने की भावना को बल मिल रहा था।

अत: हिटलर ने 1938 के आते-आते पहला समझौता रूस के साथ ही किया और अन्य करीब के यूरोपीय देशों के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू कर दिया, परन्तु हिटलर की बढ़ती ताकत से खुद रूस ही घबरा बैठा और उसने इस युद्धकाल में यूरोपीय देशों के पाले में जाना बेहतर समझा। इस युद्ध को ही द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया जिसमें रूस समेत सभी यूरोपीय ताकतों ने जर्मनी का विरोध किया केवल जापान व इटली जैसे देशों ने हिटलर का साथ दिया जिनकी 1945 के आते-आते भारी पराजय हुई और जर्मनी भी दो भागों में बंट गया, परन्तु इस युद्ध के चलते ब्रिटेन समेत अन्य साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों की ताकत खत्म सी हो गई और इसके समानान्तर अमेरिका की आर्थिक ताकत सब के सिर चढ़ कर बोलने लगी। हालत यहां तक आ गई कि ब्रिटेन के पास अपनी विशाल फौज की तनख्वाहें देने तक के पैसे नहीं बचे और अमेरिका की मदद से उसे यह काम करने को मजबूर होना पड़ा जिससे अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया ब्रिटेन अपने उपनिवेशों को खाली करे जिससे इन देशों में बढ़ते सोवियत या रूसी प्रभाव को थामा जा सके। ऐसे देशों में भारत सबसे प्रमुख राष्ट्र था अत: 1947 में इसे स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया परन्तु इसे धार्मिक आधार पर दो देशों में बांट दिया गया। इसका प्रमुख कारण यह था कि पाकिस्तान को यूरोपीय देश भविष्य में अपना 'सेवादेश' बनाकर रखना चाहते थे जिससे इसके कराची शहर से लगे अरब महासागर की मार्फत आस्ट्रेलिया तक फैले प्रशान्त महासागर तक के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रख सकें। आस्ट्रेलिया देश पर अंग्रेजों का ही प्रभुत्व था, अत: हिन्द महासागर को छूते प्रशान्त महासागर की इस जल भौगोलिकी को समझना बहुत जरूरी है जिसके चलते यूरोपीय ताकतों ने कैरिबियाई जल क्षेत्र के देशों तक में अपने उपनिवेश स्थापित किये हुए थे, परन्तु 1947 में भारत को स्वतन्त्र किये जाने के बाद इन क्षेत्रों के सभी औपनिवेशिक राष्ट्रों में आजादी की नई चेतना ने उभार लेना शुरू किया और देखतेद्धदेखते ही ये देश ब्रिटेन, फ्रान्स, नीदरलैंड व पुर्तगाल के शिकन्जे से आजादी प्राप्त करने लगे। मॉरीशस भी ऐसा ही एक देश है जो हिन्द महासागर के परिक्षेत्र में पड़ता है। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी इसी देश की तीन दिन की राजकीय यात्रा पर आजकल यहां गये हुए हैं। अत: श्री मोदी का द्विपक्षीय वार्ता के बाद यह कहना कि भारत हिन्द महासागर परिक्षेत्र को अवसरों का महासमुद्र बनाना चाहता है। पूरे महासागरीय मुल्क देशों की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने वाला है। मॉरीशस के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने श्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्राजियन आफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया। श्री मोदी ने हिन्द महासागर क्षेत्र को समुद्री अपराधों से मुक्त रखने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने व संयुक्त रणनीति बनाने पर भी जोर दिया। भारत सत्तर के दशक तक हिन्द महासागर क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय शान्ति क्षेत्र घोषित करने के पक्ष में रहा था। श्री मोदी अब बदली परिस्थितियों में इस क्षेत्र के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपसी निर्भरता के आधार पर विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं जिसके लिए स्पष्ट दूरदर्शी नीतियों की आवश्यकता है। हिन्द महासागर क्षेत्र की एक विशिष्ट शक्ति होने की वजह से भारत की नीति इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ती प्रतीत हो रही है।

नागरिकता बताएं तो बताएं कैसे!

जब से सरकार-जी की सरकार के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तब से मुझे अपने ही देश में अपनी नागरिकता फिर से याद करना पड़ रही है। अब तक मैं पूरे आत्मविश्वास से हर फॉर्म में नागरिकता वाले खाने में हिंदी में भारतीय और अंग्रेजी में इंडियन लिखता आया था। आज पता चला कि मैं यह काम वर्षों से बिना किसी प्रमाण के करता रहा हूं। यह तो अच्छा हुआ कि सरकार जी ने समय रहते बता दिया, वरना कहीं ऐसा न हो कि चालीस साल पुराने किसी फॉर्म में «भारतीय» लिखने के अपराध में मुझे झूठा घोषणा-पत्र देने का अभियुक्त बना दिया जाए, देशद्रोही मान लिया जाये। मेरे पास आधार कार्ड है। वही आधार जो सरकार जी की हर योजना के लिए जरूरी है। देश में अंदरूनी हवाई यात्रा के लिए आधार, रेल गाड़ी में मैं आने जाने के लिए आधार, होटल में कमरा बुक करवाते समय आधार, बैंक में खाता खुलवाते समय आधार, मोबाइल का सिम खरीदने के लिए आधार, गैस का कनेक्शन लेने के लिए भी आधार, हर समय आधार, सभी चीजों में आधार जरूरी है। आपके अस्तित्व का आधार है आधार। आधार वैसे तो बहुत उपयोगी है पर इतना उपयोगी भी नहीं है कि इसे नागरिकता का प्रमाणपत्र मान सकें। नागरिकता साबित करने में यह फिसड्डी है। मेरे पास भारत सरकार द्वारा दिया गया, इशू किया गया, पैन कार्ड भी है। यह बहुत वैल्यू रखता है पर इतनी भी नहीं कि यह मेरे भारत का नागरिक होने का सबूत बन सके। सरकार जी के लिए यह पैसा पाने का साधन है और मेरे लिए पैसा खोने का। इससे मैं देश की सरकार को अपनी आय पर कर (टैक्स) देता हूं। मेरे से आय कर वसूल कर सरकार जी अपनी फोटो लगे थैलों में अस्सी करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। वे हमारे लिए एक्सप्रेस बनवाते हैं जिन पर हम जिंदगी भर टोल देते देते थक जाते हैं पर उनका दोस्त टोल लेते लेते नहीं थकता है। इसी पैसे से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और पोर्ट बनवा कर सरकार जी अपने दोस्त को देते हैं कि जा दोस्त, कमा और खा। सरकार जी इस पैन कार्ड से मुझसे टैक्स तो ले लेते हैं पर मुझे देश का नागरिक मानने से इनकार कर देते हैं। मेरे पास भारत सरकार द्वारा दिया गया भारत का पासपोर्ट भी है। वही पासपोर्ट जो तरह तरह के प्रमाण पत्र देने के बाद बना है। उसमें तो पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ था। उसके बल पर मैं तीन चार बार भारी वीसा फीस दे कर देश के बाहर भी हो आया हूं। विदेश में मेरे इसी पासपोर्ट के कारण इमाइग्रेशन अफसर मुझसे कहता है, «ओह, यू आर इंडियन»। मेरे इसी पासपोर्ट के कारण वह मुझे एक तरफ कर देता है और तरह तरह के प्रश्न पूछता है। इसी पासपोर्ट की वजह से उसे संदेह है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं बस जाऊंगा। उसे संदेह मेरी नागरिकता पर नहीं, मेरे वापस जाने पर है। जिस पासपोर्ट के कारण मुझे बाकी के सारे देश इंडियन मानते हैं और उसी तरह का व्यवहार करते हैं, उस पासपोर्ट को मेरी सरकार मेरे इंडियन होने का सबूत नहीं मानती है। वह तो इसे सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट मानती है। मेरे पास वोटर कार्ड भी है। उस पर मेरी फोटो भी है और घर का पता भी। एसआईआर की कार्यवाही के बावजूद वह अभी तक बचा हुआ है। उस कार्ड की बदौलत ही मैं कई सारे चुनावों में मतदान भी कर चुका हूं। सरकार बदलने के लिए भी वोट डाल चुका हूं। वोट देने के लिए मैं पर्याप्त भारतीय हूं, लेकिन नागरिक कहलाने के लिए पर्याप्त भारतीय नहीं। लोकतंत्र को भी मेरे वोट पर भरोसा है, नागरिकता पर नहीं। इससे बड़ा और आत्मनिर्भर लोकतंत्र और क्या होगा अब सरकार जी की मर्जी है। वे जब चाहें मेरे द्वारा भरा गया कोई भी फॉर्म, भले ही वह तीस चालीस साल पहले भरा गया हो, निकाल कर पूछ सकते हैं कि तुमने नागरिकता के कॉलम में भारतीय कैसे भरा सबूत कहां है।

सिर्फ रिश्ते का ही नहीं, भरोसे का भी कत्ल

बीते कुछ वर्षों में भारतीय समाज में कुछ ऐसे आपराधिक मामले सामने आए हैं, जिन्होंने न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी गहराई से झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं की सबसे दुखद और चिंताजनक बात यह है कि अपराध को अंजाम देने वाले कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि वे लोग थे जिन पर पीड़ितों ने अटूट विश्वास किया था, चाहे पति हो, पत्नी हो या फिर मंगेतर, इन रिश्तों की पवित्रता को दरकिनार कर हत्या जैसे गंभीर अपराध किए गए हैं। पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड हालिया समय की एक ऐसी घटना है, जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। 26 वर्षीय व्यवसायी केतन अग्रवाल की मृत्यु को शुरुआत में एक ट्रैकिंग दुर्घटना समझा गया था, लेकिन पुलिस की सघन जांच में एक भयावह साजिश का खुलासा हुआ। एक युवा जिसने शादी कर नए जीवन के सपने देखे थे, आज सिर्फ एक याद बनकर रह गया। केतन अग्रवाल केस ने भरोसे, रिश्तों और प्यार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। केतन हत्या केस जैसी दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद समाज में रिश्तों और भरोसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर सोची-समझी साजिश के तहत केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देकर मारने का आरोप है। एक साल पहले मेघालय में इंदौर की सोनम रघुवंशी ने हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी पहाड़ी से धक्का देकर मौत की नींद सुला दिया था। साजिश में उसका प्रेमी राज सिंह भी शामिल था। हत्या की दोनों ही घटनाओं में प्रेम का दूसरा कोण मौजूद रहा। पहली घटना में खलनायक प्रेमी राज सिंह तो दूसरी घटना में चेतन चौधरी। दोनों ही घटनाओं में पति व मंगेतर को कांटा मानकर जीवन से हटाना और प्रेमी के दिखाए सब्जबाग संग जीने की उत्कट चाह थी, लेकिन ये कोई सामान्य दुर्घटनाएं नहीं है, एक सुनियोजित साजिश है, भरोसे के रिश्तों के कत्ल की। भारतीय समाज में ये घटनाएं अस्वाभाविक है और परिवार संस्था में भरोसा रखने वाले हर व्यक्ति को उद्वेलित करती है। यह समाज विज्ञानियों के लिए मंथन का विषय है कि कोई स्त्री कैसे अपने पति या होने वाली पति की हत्या करने की सोच बना लेती है सोच बनाती ही नहीं है बल्कि उसे सुनियोजित षड्यंत्र रचकर अंजाम भी देती है, यहां प्रश्न उठता है कि यदि सोनम व सिया परिवार द्वारा तय किए गए रिश्ते में नहीं बंधना चाहती तो न कहने का साहस तो कर ही सकती थी निश्चय ही हत्या करने से न कहना ज्यादा आसान है। धनाढ्य परिवार के केतन की तो अभी सगाई ही हुई थी, जिसे टाला भी जा सकता था। सिया के न चाहने पर परिवार के लोग केतन को खोने के बजाय रिश्ते को मन मारकर तोड़ देते। केतन मर्डर केस हो, राजा रघुवंशी हत्याकांड, सौरभ राजपूत का मामला या फिर महालक्ष्मी मर्डर केस- इन सभी में एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर पार्टनर की जान लेने की नौबत क्यों आ रही है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इसके पीछे कई अहम कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण 'सोशल स्टेटस' यानी सामाजिक रुतबा है। कई बार दो परिवारों के बीच सामाजिक हैसियत का बड़ा अंतर होता है। ऐसे में, अगर कोई महिला ऐसे रिश्ते में है जिसे उसका परिवार पसंद नहीं करता, तो सामाजिक भिन्नता के कारण परिवार वाले उस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाते। नतीजतन, महिला पर परिवार का जबरदस्त मानसिक दबाव पड़ता है। यह समाज में लंबे समय से होता आ रहा है और आज भी कई महिलाएं इस तरह के भारी दबाव के बीच जी रही हैं। जब परिवार वाले किसी रिश्ते के सख्त खिलाफ होते है, तो व्यक्ति को अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए एक मजबूत स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। परिवार के सामने अपनी बात न रख पाना एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जो हालात को बद से बदतर कर देता है। जब लोग स्टैंड नहीं ले पाते, तो वे अंदर ही अंदर बुरी तरह आहत होते रहते हैं और घुटने लगते हैं।

इस घुटन की वजह से उनके भीतर भयंकर गुस्सा पनपता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और उनके मूड में काफी उतार-चढ़ाव आने लगते हैं। जब वे इन हालातों से तालमेल नहीं बिठा पाते या उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते, तो ये नकारात्मक भावनाएं उन पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि वे मर्डर जैसा खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर महसूस करने लगते हैं। हमारे समाज में वैवाहिक रिश्तों में पैदा होने वाली हिंसा, टकराव, अलगाव और कोर्ट-कचहरी का ट्रेंड गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। सवाल यह है कि नौ महीने कोख में रखने वाली मां और खून-पसीने से लालन-पालन करने वाले पिता के सोचे-विचारे फैसलों को नई पीढ़ी द्वारा क्यों खारिज किया जा रहा है क्या समाज में दूषित खानपान, विघातक सोच का बाजार, रिश्तों में बढ़ता अविश्वास और एकाकी परिवारों का त्रास युवा पीढ़ी को आक्रामक बना रहा है मोबाइल संस्कृति की घातकता व तेजी से फैलता नकारात्मक कंटेंट संबंधों में विकृतियां ला रहा है।

मोबाइल फोन जो कभी रिश्तों को जोड़ता था, अपराध का साधन बन रहा है। सोनम व राज सिंह की साजिश हो या सिया व चेतन का षड्यंत्र, उसमें मोबाइल भी सहभागी बना है। केतन की हत्या केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि विश्वास, रिश्तों और इंसानियत की भी हत्या है! सच्चाई क्या है, यह जांच और अदालत तय करेगी, लेकिन इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी कितनी जरूरी है ऐसी त्रासदियों के बीच रिश्तों में दोबारा विश्वास कायम करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए, समाज और परिवारों को इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा, यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्ते या शादी से खुश नहीं है, तो उसे समाज या परिवार के डर से घुटने के बजाय खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। शादी तोड़ने का रास्ता चुनना किसी की जान लेने या किसी की जिंदगी बर्बाद करने से हमेशा बेहतर और आसान विकल्प है। वहीं नए रिश्तों में कदम रखने से पहले पार्टनर को अपने अतीत और वर्तमान की प्राथमिकताओं के बारे में पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। यह सच है कि इस तरह की घटनाएं समाज को डराती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया से अच्छाई खत्म हो गई है। ऐसी दुखद और नेगेटिव घटनाएं इक्का-दुक्का ही होती हैं लेकिन ये अप्रत्याशित व असामान्य घटनाएं आम आदमी की सोच खासकर युवाओं को अंदर तक असर डालती है, जो समाज में सहज-सरल रिश्तों के प्रति अविश्वास पैदा करती है। ऐसी सोच का नेगेटिव नतीजा भारतीय आदर्श स्त्री की प्रतिष्ठा पर भी आंच ला सकता है। यही कारण है कि नई पीढ़ी के कई युवा विवाह संस्था में प्रवेश से कतराने लगे हैं। जरूरत इस बात की है कि, रिश्तों में अंधा भरोसा करने की जगह सजगता, आपसी सम्मान, और खुलकर बात करने की आदत ही आज के समय में हमारे भरोसे को सुरक्षित रख सकती है। ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। जब अपराधियों को उनके किए की सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तभी समाज में एक डर पैदा होगा और लोगों का न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घिल्डी ने कल्पना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सदा पब्लिकेशन एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार घिल्डी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

सीएम योगी बोले- आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं, जनता को सपा-कांग्रेस के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं

लखनऊ ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले दंगों और कर्फ्यू की आग में झुलसते थे। कैराना व कांधला से पलायन की स्थिति थी, बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार दंगाइयों और उपद्रवियों के मुकदमे वापस लेने का कुत्सित प्रयास करती थी। लेकिन डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया और हाल में मुरादाबाद के उपद्रवियों को कड़ी सजा भी दिलवाई है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, बल्कि विकास की योजनाएं धरातल पर उतरती हैं।

आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं

सीएम ने कहा कि जाति व क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। वे कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। वे काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा-वृंदावन, श्रीराम मंदिर का विरोध कर रहे थे। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम व श्रीकृष्ण हुए ही नहीं। रामभक्तों पर गोलियां चलवाने वाले आस्था पर उपदेश दे रहे हैं! आस्था के साथ कोई खिलवाड़ स्वीकार नहीं है, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

वैश्विक पटल पर चमक रही अयोध्या

सीएम ने कहा कि कभी संकरी गलियों व अव्यवस्था की पहचान बन चुकी अयोध्या में आज चारों ओर से फोर लेन कनेक्टिविटी है। ब्रॉडगेज की डबल लाइन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। सपा को चार बार सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन उसने अयोध्या धाम के लिए कुछ नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में अयोध्या धाम त्रेतायुग की दिव्यता व भव्यता के साथ वैश्विक पटल पर

चमक रहा है। संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि व बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जैसे महापुरुषों की विरोधी समाजवादी पार्टी व कांग्रेस ने सिर्फ अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाने का काम किया।

2017 से पहले दंगा-पलायन थी पहचान

सीएम योगी कहा कि 2017 से पहले दंगा, कर्फ्यू हमारी नियति बन गई थी। कैराना व कांधला से पलायन होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बेटी व व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। कानून-व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। 2011 में मुरादाबाद में डीआईजी पर हमला किया गया। उपद्रवी उन्हें मरा हुआ समझ छोड़कर चले गए। सपा सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके केस वापस लेने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार ने उन सभी उपद्रवियों को सजा दिलाई। मजबूत कानून-व्यवस्था अब यूपी की नई पहचान है।

कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में लगता था पैसा

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के नेताओं के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उनकी आस्था तब कहां थी जब कांवड़ यात्राओं, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और दुर्गा पूजा के पंडालों पर प्रतिबंध लगाए जाते थे और विकास का पैसा या तो सपा के गुर्गों द्वारा खा लिया जाता था या कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में खर्च हो जाता था।

आज वही पैसा मां शाकंभरी कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, फोर व टू लेन सड़क, पुल, विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स कॉलेज, सरसावा में सिविल टर्मिनल निर्माण, रनवे की लंबाई बढ़ाने और वुड कार्विंग के कारीगरों का जीवन स्तर उठाने में खर्च हो रहा है। यह दृष्टिकोण का अंतर है। सपा को केवल सैफई की चिंता होती थी, जबकि डबल इंजन सरकार सभी 75 जनपदों, 1,07,000 गांवों, 57,000 ग्राम पंचायतों, 825 विकास खंडों, 12,000 वार्डों और 762 नगर निकायों की चिंता करती है।

मां शाकंभरी देवी का भव्य एलिवेटेड कॉरिडोर

धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुद्धार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मां शाकंभरी देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए एक भव्य एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले दिनों शिवालिक की पहाड़ियों में अचानक हुई भारी वर्षा के दौरान प्रशासनिक मुस्तैदी और समय पर जारी अलर्ट के कारण जन-धन की हानि रोकने में सफलता मिली थी। भविष्य में मौसम चाहे कैसा भी हो, श्रद्धालुओं का आवागमन बाधित न हो, इसके लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और बेहतरीन फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जो पहले की सरकारों के लिए सपना था।

प्रदेश में बढ़ा मानसून का जोर, इन 24 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी; यहां के लिए वज्रपात का अलर्ट

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय होते ही बुधवार को तराई समेत कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। बारिश से कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून के छा जाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को बहराइच में सर्वाधिक 113 मिमी और बिजनौर में 95 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

इसके अलावा ललितपुर में 93 मिमी, बुलंदशहर में 72 मिमी तथा संभल और हमीरपुर में 65-65 मिमी बारिश हुई। वाराणसी, हरदोई, मुरादाबाद समेत कई अन्य जिलों में भी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार के लिए बांदा, प्रयागराज, सोनभद्र, मेरठ, रामपुर, बरेली समेत 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बांदा, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी सहित 28 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों में मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा।

इन जिलों में है भारी वर्षा की चेतावनी

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के क्षेत्र।

यहां है वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के क्षेत्र।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी- एकांतवास में चंपत राय बोले- कलंक लेकर नहीं जाऊंगा, अयोध्या में सेवा हुई पूरी

लखनऊ । राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को लेकर नया घटनाक्रम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, एकांतवास में रह रहे चंपत राय ने अपने कुछ करीबियों से बातचीत में कहा कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो गई है और वह कलंक लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके भरोसे के साथ विश्वासघात हुआ है। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी जांच के दौरान चंपत राय राम मंदिर परिसर स्थित तीर्थ क्षेत्र भवन के ऊपरी हिस्से में ही रह रहे हैं। जब से जांच शुरू हुई है तब से वह यहीं पर हैं। चढ़ावा चोरी प्रकरण सामने आने के बाद से चंपत लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं। मामले की जांच जारी रहने के बीच उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तब से उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि उन्होंने करीबियों से चोरी प्रकरण में कई बातें कही हैं। जिसमें ये भी कहा कि उनकी इसमें भूमिका नहीं रही। जिस दिन पता चला कि ऐसा हो रहा है तुरंत कार्रवाई शुरू की गई।

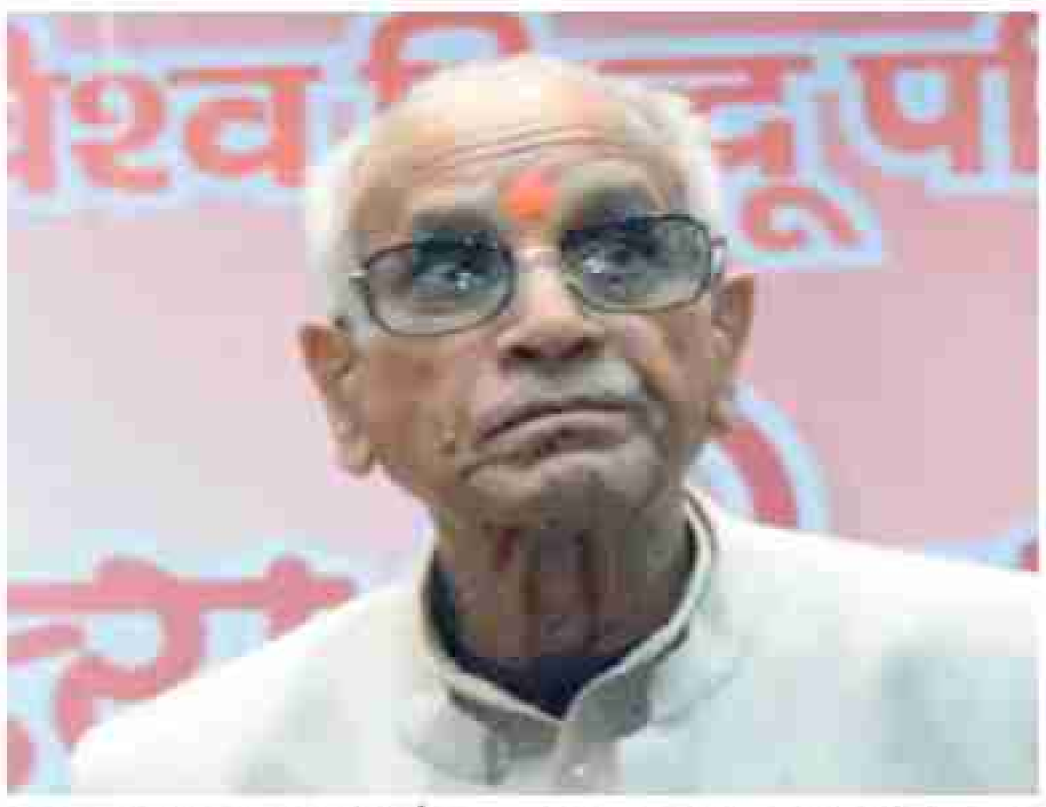

संघ की रिपोर्ट तैयार, आला कमान को भेजा गया फीडबैक

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण से उपजे हालात को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भी सक्रिय है। सूत्रों के अनुसार, संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने लगभग एक सप्ताह तक अयोध्या में प्रवास कर पूरे घटनाक्रम का फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने साधु-संतों, सामाजिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न पक्षों से बातचीत कर स्थिति का आकलन किया। बताया जा रहा है कि इस आधार पर तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट संघ के शीर्ष नेतृत्व को भेज दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक, राम मंदिर में चढ़ावे की गणना और प्रबंधन से जुड़ी कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद संघ ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। इसी क्रम में क्षेत्र प्रचारक अनिल, प्रांत प्रचारक कौशल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी अयोध्या पहुंचे। आधिकारिक तौर पर उनका दौरा संघ के एक वर्ग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बताया गया, लेकिन प्रवास के दौरान उन्होंने विभिन्न स्तरों पर लोगों से मुलाकात कर फीडबैक भी जुटाया। बताया जाता है कि इस दौरान संत समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों, रामभक्तों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और मंदिर व्यवस्था से जुड़े जानकारों से अलग-अलग बातचीत की गई। बातचीत के दौरान यह जानने का प्रयास किया गया कि चढ़ावा प्रकरण को लेकर उनकी क्या राय है और राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली के प्रति उनकी क्या धारणा बनी है। सूत्रों के अनुसार, फीडबैक के दौरान ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, चढ़ावे की गणना प्रक्रिया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सभी प्रतिक्रियाओं और तथ्यों को संकलित कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे संघ के शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर संगठन स्तर पर आगे आवश्यक सुझाव या निर्णय लिए जा सकते हैं।

तीन दिन चलने वाली यूपी टीईटी आज से, 60 जिलों में 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल; बनाए गए हैं 955 केंद्र

लखनऊ । उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दो, तीन और चार जुलाई को आयोजित होगी। इसमें प्रदेश के 60 जिलों से करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों से भी एक लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा कुल 955 केंद्रों पर होगी। महाराष्ट्र में टीईटी का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों ने सैकड़ों कोचिंग संचालकों के नंबर निगरानी पर लिए हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने परीक्षा पारदर्शिता और निष्पक्षता से कराने की बात कही। वर्ष 2021 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से कराई गई टीईटी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया था। इसी कारण इस बार एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं।

पांच पालियों में होगा परीक्षा का आयोजन

- परीक्षा का आयोजन 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर कुल 5 पालियों में होगा
- 2 जुलाई को उच्च प्राथमिक स्तर, 3 जुलाई को प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक तथा द्वितीय पाली में प्राथमिक स्तर तथा 4 जुलाई को प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी
- परीक्षा में कुल 19,94,661 अभ्यर्थी शामिल होंगे, इनमें 17,67,180 अभ्यर्थी यूपी के, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों के हैं
- परीक्षा में 1,85,791 सेवारत शिक्षक तथा 18,08,870 नए अभ्यर्थी शामिल होंगे
- प्राथमिक स्तर के लिए 3,88,179, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 8,16,436 तथा दोनों स्तरों के लिए 3,95,023 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है- सर्वाधिक परीक्षा केंद्र एवं अभ्यर्थियों वाले जिलों में वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, मेरठ, मऊ, मुरादाबाद, आगरा तथा जौनपुर शामिल हैं।

टीईटी के लिए जौनपुर से सबसे अधिक 67597 और लद्दाख से सबसे कम एक अभ्यर्थी पंजीकृत है। बिहार से 31766, मध्य प्रदेश से 20375, दिल्ली से 16411 और राजस्थान से 12774 अभ्यर्थी शामिल होंगे। हरियाणा से 5748, झारखंड से 5635, उत्तराखंड से 2710 और पश्चिम बंगाल से 1909 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को विशेष सुविधा

इस बारे में निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ अन्य राज्यों से भी आएंगे। ऐसे में रेलवे स्टेशन, बस अड्डों तथा प्रमुख यातायात केन्द्रों पर पर्याप्त सहायता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

परिवहन निगम, रेलवे तथा आवश्यकतानुसार निजी स्थानीय परिवहन संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। परीक्षा के पूर्व एवं पश्चात संभावित भीड़ को देखते हुए प्रभावी यातायात प्रबंधन किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बड़ी संख्या में युवाओं के आवागमन के दौरान खाद्य एवं पेय पदार्थों के मूल्य अनावश्यक रूप से न बढ़ाए जाएं।

राहुल की अमित शाह पर विवादित टिप्पणी पर दोनों पक्षों ने की बहस, 15 जुलाई को आ सकता है फैसला

लखनऊ । गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में आवाज नमूने की जांच के लिए भाजपा नेता की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में लंबित निगरानी याचिका में दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी बहस की कार्यवाही पूरी कर दी है। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने निगरानी याचिका पर आदेश के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं, स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में मानहानि के मूल मुकदमे में सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख तय की है।कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का परिवार दायर किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित चल रही है। पूर्व में अदालत ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही तय की थी। इसी बीच गत 12 मार्च को विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दी गई थी। अदालत ने परिवादी की अर्जी को गत दो मई को खारिज करते हुए पूर्व में जारी कार्यवाही के अनुसार बहस करने व जमानत नामा पेश करने का आदेश जारी किया था, लेकिन परिवादी भाजपा नेता ने मामले में बहस करने के बजाय मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में निगरानी पेश कर चुनौती दी है। अदालत ने बहस सुनने के बाद निगरानी याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।

भीषण गर्मी से पक्षियों, वन्यजीवों पर मंडराया संकट, अप्रैल से अब तक 224 को बचाया गया

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव का असर अब सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पक्षियों और वन्यजीवों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और पानी की कमी के कारण बड़ी संख्या में पक्षी और अन्य वन्यजीव बीमार हो रहे हैं। गर्मी से उन्हें डायरिया और सूखा रोग की समस्या हो रही है। इससे वह खाना-पीना पूरी तरह से नहीं खा रहे है। ऐसे में उनका शरीर साथ छोड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि इनमें से कई पक्षी आसमान में उड़ान भरने से मोहताज हो रहे हैं, तो कुछ अपने घोंसलों में नहीं जा पा रहे हैं। कई पक्षी तो मौत के शिकार भी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा असर युवा चील (यंग काइट्स), कबूतर और अन्य शहरी पक्षियों पर पड़ रहा है। गर्म हवाओं में उड़ान भरने वाले पक्षी थोड़ी सी दूरी तय कर जमीन पर गिरने से जख्मी हो रहे हैं। पशु-पक्षी अस्पताल में लोग प्रतिदिन हिट स्ट्रोक से घायल पक्षियों बड़ी संख्या में लेकर पहुंच रहे हैं। वाइल्डलाइफ एसओएस के अनुसार, अप्रैल से अब तक 224 पक्षियों और वन्यजीवों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि इस साल अप्रैल में ही रेस्क्यू मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में 39.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संस्था के मुताबिक, सामान्य दिनों में जहां रोजाना 5 से 10 रेस्क्यू कॉल मिलती थीं। वहीं, इन दिनों यह संख्या बढ़कर 15 से 20 कॉल प्रतिदिन हो गई है। सबसे अधिक मामले हीट स्ट्रोक, शरीर में पानी की कमी से घोंसलों से गिरने वाले पक्षियों और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे सांप, गोह समेत अन्य सरीसृपों के सामने आ रहे हैं। चांदनी चौक के दिगंबर जैन लाल मंदिर में स्थित पक्षियों का धर्मार्थ चिकित्सालय में हर दिन बीमार और जख्मी परिंदे पहुंच रहे हैं। डॉ. हरअवतार सिंह बताया कि गर्मी पक्षियों के लिए घातक बन रही है। ज्यादा तापमान होने की वजह से पक्षियों को भी ग्लूकोज और विटामिन की कमी हो रही है। पानी के लिए गंदे नालों के अलावा लंबे समय तक रखे गए पानी का सेवन करना इनकी मजबूरी बन रही है। ऐसे में इस जल का सेवन करने से वे चेचक और आंखों की रोशनी प्रभावित हो रहे हैं। चिकित्सक डॉ. हरअवतार सिंह का कहना है कि पक्षियों के लिए आदर्श तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। इससे अधिक तापमान घातक है। गर्मी की वजह से खुले में पक्षियों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर किसी को गर्मी से घायल पशु-पक्षी दिखते है, तो उन पर पहले ठंडे पानी का छिड़काव करें। उनके पंजों को कुछ देर के लिए ठंडे पानी में डाल दें। इसके बाद उन्हें छांव में ले जाएं। उन्हें ऐसे स्थान पर रखें जहां हवा अच्छी स्तर में हो। दिल्ली में अगले छह दिन मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 1 जुलाई को तापमान घटकर 35 से 37 डिग्री और 2 जुलाई को 34 से 36 डिग्री तक रहने का अनुमान है। इन दोनों दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने इन तीन दिनों के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

भारत-पाक की 117 प्रमुख हस्तियों ने मोदी-शहबाज को पत्र लिखा

बोले- दुश्मनी खत्म करें, बातचीत और रिश्ते फिर शुरू हों

नई दिल्ली/इस्लामाबाद। भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए, ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोगों और पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किए हैं। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब हाल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है। इनका कहना है कि लगातार बढ़ती शत्रुता से दोनों देशों के विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं।

दिल्ली-बुंदेलखंड को कैबिनेट की बड़ी सौगात, 6 लेन का द्वारका टनल, कानपुर से कबरई तक 4 लेन हाईवे

नई दिल्ली। केन्द्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को दो ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ट्रैफिक समस्या कम करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सड़क संपर्क भी पहले से कहीं ज्यादा तेज और बेहतर हो जाएगा। कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला दिल्ली के लिए है. कैबिनेट ने करीब 6,970 करोड़ रुपये की लागत से 8 किलोमीटर लंबी छह-लेन द्वारका टनल के निर्माण को मंजूरी दी है. यह टनल शिवमूर्ति से वसंत कुंज होते हुए बारापुला के पास तक बनाई जाएगी. परियोजना को पूरा करने में लगभग पांच साल का समय लगेगा. इस

टनल के बनने से दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और एयरपोर्ट के साथ ही प्रमुख इलाकों के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा. केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहला प्रोजेक्ट 2-लेन द्वारका टनल है. यह दिल्ली के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. 8 किलोमीटर लंबी यह टनल एक पुरानी मांग को पूरा करेगी. दूसरा बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए है. कैबिनेट ने कानपुर से कबरई तक 242 किलोमीटर लंबे फोर-लेन हाईवे को मंजूरी दी है. इस परियोजना की लागत 7,145 करोड़ रुपये होगी और इसे करीब ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

आगे चलकर यह सड़क भोपाल तक बेहतर सड़क संपर्क का हिस्सा बनेगी.

इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा यात्रा समय में भारी कमी के रूप में देखने को मिलेगा. फिलहाल कानपुर से कबरई तक का सफर करीब साढ़े तीन घंटे में पूरा होता है, लेकिन नई फोर-लेन सड़क बनने के बाद यही दूरी करीब डेढ़ घंटे में तय की जा सकेगी. अश्विनी वैष्णव ने कहा, दूसरा प्रोजेक्ट (जिसकी घोषणा आज केंद्र सरकार ने की है) यूपी के बुंदेलखंड इलाके को जोड़ता है. यह कानपुर से भोपाल के बीच के हिस्से को कवर करता है. आज जिस हिस्से को मंजूरी मिली है,

वह कानपुर से कबरई तक 242 किलोमीटर लंबा है. इससे न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि माल परिवहन, व्यापार और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. इन दोनों परियोजनाओं के जरिए केंद्र सरकार का फोकस शहरी ट्रैफिक सुधारने, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को मजबूत करने और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच तेज, सुरक्षित और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर है.

राजस्थान में बस-ट्रेलर भिड़े, 8 मौतें, डीएनए टेस्ट से पहचान होगी

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में मंगलवार देर रात बस-ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 6 लोगों की मौत आग में झुलसने से और 2 की सिर पर चोट लगने के कारण हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक्सीडेंट कोलवा थाना क्षेत्र में हुआ है। बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी स्लीपर में मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों के 40 पैसेंजर्स थे। इनमें 21 लोग घायल भी है। 6 मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद बॉडी परिवार को सौंपी जाएगी। बस में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं, स्थानीय ग्रामीणों का दावा है बस के स्टोरेज बॉक्स में सिगरेट भरी हुई थी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी- आरोपी अविनाश शुक्ला के कमरे में मिला रामराय कोष का संदूक, क्यूआर कोड भी लगा

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस जांच लगातार जारी है। आरोपियों से जेल में पूछताछ की जा रही है वहीं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी भी की जा रही है। मामले में अभी तक 80 लाख रुपये तक की बरामदगी का दावा किया गया है। जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी अविनाश शुक्ला के कमरे से एक संदूक बरामद किया है जिस पर रामराय कोष लिखा हुआ है और इस पर पेटीएम का स्कैन कोड भी लगा हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां पर मौजूद श्याम साधनालय की योगाचार्य सीमा तिवारी ने अमर उजाला से बातचीत में बताया कि अविनाश शुक्ला पिछले करीब डेढ़ वर्ष से अयोध्या में रह रहे थे और राम मंदिर से जुड़ी गतिविधियों में कार्यरत थे। उनके अनुसार, अविनाश का परिचय योग गुरु डॉ. चैतन्य और उनके भाई अभिषेक के माध्यम से हुआ था। वहीं, 5 जून के प्रत्यक्षदर्शी सेवादार सुंदरलाल ने बताया कि उस दिन पुलिस कुछ लोगों के साथ अविनाश को किराये के मकान पर लेकर आई थी। उनके अनुसार, घर से एक बैग निकाला गया, जिसमें कुछ नकदी थी। इसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया और पुलिस अविनाश को अपने साथ ले गई। हालांकि, इन बयानों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब तक बरामद नकदी या उसके स्रोत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।

तमिलनाडु में 35 करोड़ की डील का दावा- विधायक ने रिश्वत और धमकी का लगाया आरोप, 3 गिरफ्तार

चेन्नई। तमिलनाडु में राजनीतिक खरीद-फरोख्त की कथित कोशिश का मामला सामने आया है। विधायक एन. एलैयाराजा ने दावा किया कि उन्हें एक विधायी प्रस्ताव पर वोट प्रभावित करने के लिए 35 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्ताव ठुकराने पर उन्हें धमकियां भी दी गईं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त के पास 29 जून को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, एलैयाराजा ने बताया कि थिरुनावुक्करासु नाम के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया। उसने दावा किया कि वह इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज नामक एक ओपिनियन पोलिंग संस्था चलाता है और एक बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों के कहने पर उनसे मिलने आया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में थिरुनावुक्करासु ने उनसे तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ प्रस्तावित प्रस्ताव पर एक खास

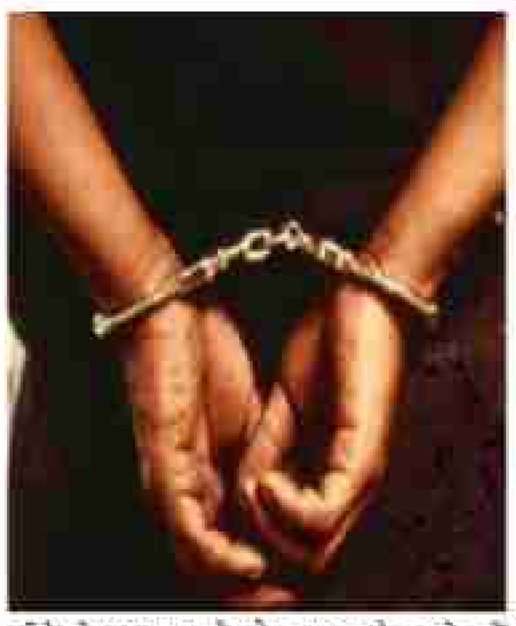

तरीके से मतदान करने को कहा। इसके बदले उन्हें 35 करोड़ रुपये तक की रिश्वत देने की पेशकश की गई। एलैयाराजा का आरोप है कि जब उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उन्हें धमकियां दी गईं और पूरी बातचीत को किसी के सामने उजागर न करने की चेतावनी भी दी गई। शिकायत मिलने के बाद डी-1 ट्रिप्लिकेन पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चेन्नई के अरुंबक्कम निवासी थिरुनावुक्करासु, तिरुचिरापल्ली निवासी नरेश और चेन्नई के मेदावक्कम निवासी त्यागराजन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, ये तीनों कथित साजिश में शामिल थे।

जांच में और किसके नाम आए सामने?

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि पूर्व डीएमके मंत्री और कोयंबटूर दक्षिण से मौजूदा विधायक वी. सेंथिल बालाजी के भाई वी. अशोक कुमार ने चेन्नई में आरोपी नरेश से मुलाकात की थी। पुलिस के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया है कि थिरुनावुक्करासु कथित तौर पर वी. सेंथिल बालाजी और वी. अशोक कुमार से जुड़े निर्देशों के आधार पर काम कर रहा था। हालांकि, इस संबंध में जांच अभी जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलपति विजय सरकार, गो-हत्या पर रोक हटाने की मांग

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि बकरीद या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो। सरकार का तर्क है कि इस फैसले से एक तरह की पूरी पाबंदी लग जाती है, जिसकी व्यवस्था मौजूदा कानून में नहीं है। अपनी स्पेशल लीव पिटिशन में राज्य ने तर्क दिया है कि हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में व्यापक प्रतिबंध लगाकर मूल जनहित याचिका के दायरे का उल्लंघन किया है, जबकि याचिका कोयंबटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गायों की हत्या को रोकने तक ही सीमित थी। यह अपील मद्रास हाई कोर्ट के 27 मई, 2026 के उस फैसले को चुनौती देती है, जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और वी. लक्ष्मीनारायण की डिवीजन बेंच ने सुनाया था। तमिलनाडु सरकार के अनुसार, PIL में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए थे कि जानवरों को मारने का काम केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही हो, न कि सार्वजनिक जगहों पर। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने पहले ही निगरानी बढ़ा दी है, तय बूचड़खानों की पहचान कर ली है, निरीक्षण के लिए अधिकारी तैनात किए हैं और सार्वजनिक जगहों पर जानवरों को मारने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। हालांकि, यह देखते हुए कि जानवरों को काटने का काम सिर्फ अधिकृत बूचड़खानों में ही होना चाहिए, हाई कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े को न काटा जाए।

नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी पीएम, बिहार के लोग यही चाहते हैं, आरजेडी के बाद जेडीयू की मांग

पटना। बिहार में आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने मांग कर दी है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए. जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग भी यही चाहते हैं. पंकज मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के सीएम रहे. उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे, ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए. जेडीयू विधायक ने कहा, ऐसा सुने हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. नीतीश कुमार तो मंत्री केंद्र में रह चुके है. इसलिए डिप्टी पीएम बनाया जाए, यही उचित सम्मान होगा. इससे पहले आरजेडी के सीनियर लीडर मुकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए. उन्होंने कहा कि कृषि और रेलवे जैसे अहम मंत्रालय नीतीश कुमार को मिले और उप-प्रधानमंत्री भी बनाया जाए. आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार के लिए यह गौरव की बात होगी. दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें है. ऐसे में जेडीयू ने मौका देखते हुए नीतीश कुमार का नाम उछाल दिया है. नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सदस्य है और जेडीयू की कमान उनके हाथों है. उनके बेटे निशांत कुमार बिहार में स्वास्थ्य मंत्री है. बता दें कि नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. 10 अप्रैल को राज्यसभा के लिए चुने गए. 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी का सीएम बनना बड़ी बात रही क्योंकि पहली बार राज्य में पार्टी को ये पद मिला.

चिकित्सक दिवस पर शुभेंदु अधिकारी का हमला, बोले- पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्था बिगाड़ी

बंगाल। चिकित्सक दिवस के मौके पर, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को जर्जर हालत में छोड़ दिया था और उनकी सरकार इसके नतीजों से निपट रही है। यह दिन मशहूर चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों एक जुलाई को ही आती हैं। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों की हालत की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, क्या राज्य के अस्पतालों की यह खराब हालत सही है? पश्चिम बंगाल में दुनिया के किसी भी देश से मुकाबला करने की काबिलियत है। लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ? राज्य के स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर को फिर से बेहतर बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का

आह्वान करते हुए, राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री ने सभी से राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को जर्जर हालत से बाहर निकालने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। अधिकारी ने कहा, हमें राज्य की स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को फिर से बेहतर बनाना होगा। मैं सभी से इसके लिए एकजुट होने की अपील करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पहल लागू करने की कोशिश करते समय उन्हें लगातार उस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसे उन्होंने बरसों से चले आ रहे प्रशासनिक पतन का नतीजा बताया। अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की एक टिप्पणी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, (ज्योति) बसु ने कहा था कि वे जहां भी काम शुरू करना चाहते थे, उन्हें पता चलता था कि डॉ. रॉय ने पहले ही उसकी नींव रख दी है। मेरी स्थिति इसके उलट है। मैं जहां भी काम शुरू करना चाहता हूं, मुझे बर्बादी ही मिलती है।

जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटा बादल- फसलें, बाग-बगीचे और संपत्ति को भारी नुकसान

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश और बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापक स्तर पर फसलों, बाग-बगीचों और निजी संपत्ति को हानि पहुंची है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। डोडा जिले के भलेसा के खलजुगासर इलाके में दो बार बादल फटने की घटना हुई है। इससे अचानक आई बाढ़ ने कृषि भूमि को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसानों की खड़ी फसलें और फलदार बाग-बगीचे पूरी तरह बर्बाद हो गए। कई मकानों और अन्य निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई। इससे भलेसा का भट्यास इलाका घंटों तक शेष क्षेत्रों

मलबा आने से कई सड़कें हुईं बंद

से कटा रहा। डोडा जिले के कस्तीगढ़ क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण यहां अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। हालांकि, कस्तीगढ़ में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

मलबे से सड़कें जाम और गांवों का संपर्क टूटा

मिली जानकारी के मुताबिक, अचानक आई बाढ़ के साथ भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और पेड़ बहकर सड़कों पर आ गए। इससे भलेसा पट्टी के कई गांवों का संपर्क

पूरी तरह कट गया है। इन गांवों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने की चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़कों की बहाली का काम तभी शुरू किया जाएगा, जब मौसम की स्थिति में सुधार होगा और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़कें पूरी तरह से धंस गई हैं, जिससे मरम्मत में समय लग सकता है। बादल फटने से क्षेत्र में कई जल स्रोत उफान पर आ गए। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया और मिट्टी का कटाव भी हुआ। सड़कों के बंद होने से आवश्यक सेवाओं की आवाजाही बाधित हुई। स्थानीय लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने सड़कों को खोलने के लिए मशीनरी लगाई है।

डोडा में आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात

प्रशासन ने डोडा जिले में आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय कर दिया है। ये टीमें प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी कर रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लगातार बारिश के कारण बचाव और राहत कार्यों में बाधा आ रही है, लेकिन अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश की जा रही है।

स्थानीय लोगों को सलाह

प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को सलाह दी है कि वे जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं हो जाता, तब तक संवेदनशील इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचें। लोगों से आधिकारिक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है। उन्हें भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लेने की सलाह दी गई है। आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने के लिए भी कहा गया है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर के बाद लगी आग, जिंदा जले 3 लोग

आंध्र प्रदेश के बोयापालेम से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां आज सुबह दो ट्रकों के बीच जोरदार आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में अचानक भयानक आग लग गई जिसकी चपेट में आने से तीन लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने इस भीषण दुर्घटना की पुष्टि की है। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब छह बजे बोयापालेम गांव में हुई और हादसे के बाद एक ट्रक में लदे कागजों ने आग पकड़ ली। इस मौके पर अधिकारी ने कहा, दोनों ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर के बाद लगी आग में तीन लोगों की जलकर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।